ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (NREGA) की भूमिका

* डा॰ जयश्री भारद्वाज
* डा. शरद चन्द्र

साराश : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) जिसे 2005 मे लागू किया गया, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबो को रोजगार का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत श्रम-प्रधान कार्यों जैसे- जल संरक्षण, तालाब निर्माण,सडक एवं सिंचाई विकास, वृक्षारोपण और भूमि सुधार के माध्यम से ग्रामीणो को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।इसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन, महिलाओ की भागीदारी मे वृद्धी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और पलायन पर नियंत्रण संभव हुआ है। यदि पारदर्शिता, वित्तीय मजबूती और कार्यो की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएँ तो नरेगा आगे आने वाले वर्षो में भारत के ग्रामीण समाज को आत्म निर्भर, सशक्त और एक सम्मान जनक जीवन जीने की दिशा मे निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

शब्द कुंजी :
औद्योगीकरण, जीवन रेखा, अदृश्य बेरोजगारी, नरेगा, सतत विकास, काम का अधिकार, सीमांत किसान, लोकतंत्र, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता डिजिटल पेमेंट ।

कृषि समस्त उद्योगो की जननी तथा औद्योगीकरण का मूल आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ कृषि व्यवसाय प्रधान है। राष्ट्रीय आय, रोजगार, निर्यात, कच्चा माल, उत्पादन एवं देश की आन्तरिक मांग की दृष्टि से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है भले ही भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है फिर भी कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली भारत के पिछडेपन की गाथा गाती है। ग्रामीण विकास मे सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण व्यक्ति का बेरोजगार होना है जैसा कि सर्वविदित है कि भारत की लगभग 56 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर है। कृषि अपने स्वरूप से ही मौसमी व्यवस्था है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर व्यक्ति मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी व खुली बेरोजगारी से पीडित रहता है। भारत मे सीमित भूमि की उपलब्धता बेरोजगारी का एक अहम कारण है। वर्तमान में देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथा इसका दबाब भूमि पर लगातार बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा का अनुपात कम होता जा रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार गाँव है यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। ग्रामीण समाज में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और अविकास जैसी समस्याएं लम्बे समय से बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद अनेक योजनाएं चलाई गयी लेकिन फिर भी ग्रामीण गरीबो की आजीविका सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती बनी रही। इस पृष्ठभूमि मे 2005 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (नरेगा)" लागू किया, जिसे बाद मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कहा गया। इस कानून का उद्देश्य केवल रोजगार देना ही नही था बल्कि ग्रामीण ढांचे को मजबूत करना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना और सतत विकास की दिशा मे कदम बढ़ाना भी था। नरेगा ग्रामीण विकास की दिशा मे सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसका सीधा संबंध ग्रामीण परिवारो की आय, सामाजिक समानता और बुनियादी ढांचे से है। जब ग्रामीण मजदूरो को गाँव मे ही काम मिलने लगा तो पलायन कम हुआ, खेती और अन्य सहायक उत्पादक कार्यों को सहारा मिला और ग्रामीण गरीबो की आर्थिक स्थिति मे सुधार आया।

नरेगा की मूल भावना :

नरेगा की मूल भावना 'काम का अधिकार' पर आधारित है। यह दुनिया का पहला कानून है जिसने काम को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी। यदि कोई व्यक्ति काम मागता है और सरकार उसे 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नही कराती तो सरकार को उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है इस प्रकार यह योजना ग्रामीण गरीबो के लिये सामाजिक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन :

भारत के गाँवो में रोजगार के अवसर सीमित रहे है। अधिकांश किसान या तो भूमिहीन है या सीमांत किसान है। कृषि मे मौसमी रोजगार ही प्राप्त होता है। ऐसे में नरेगा ने उन्हें अतिरिक्त काम उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि की। कई अध्ययनो से स्पष्ट हुआ है कि नरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दर को बढ़ाया और महिलाओ तथा कमजोर वर्गो की स्थिति मजबूत की। इससे गरीबी घटाने और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिली।

महिला सशक्तिकरण :

नरेगा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमे एक तिहाई रोजगार महिलाओ के लिये आरक्षित है, लेकिन व्यवहार में कई राज्यो में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक रही है। महिलाओ की मजदूरी सीधे बैंक खाते में जमा होने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मे वृद्धि हुई। गाँवो की महिलाएं पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहती थी, अब वे सार्वजनिक कामों में भी भागीदारी कर रही है। इससे न केवल उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी वरन ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता की दिशा मे भी सकारात्मक परिवर्तन आया।

पलायन पर नियंत्रण :

नरेगा लागू होने से पहले बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण मजदूर रोजगार की तलाश मे शहरो की ओर पलायन करते थे। इससे न केवल परिवारो का सामाजिक ढाचा प्रभावित होता था वरन शहरो में झुग्गी-झोपड़ियो और मलिन बस्तियो का विस्तार भी होता था। नरेगा ने गाँव मे ही काम उपलब्ध कराकर इस प्रवृत्ति को काफी हद तक कम किया। अब ग्रामीण परिवार अपने घर-गाँव में रहकर रोजगार पाकर अपना जीवन यापन भली प्रकार कर सकते है।

ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण :

नरेगा के अन्तर्गत जो कार्य किये जाते है वे अधिकांशतः श्रम- प्रधान और ग्रामीण विकास उन्मुख होते है जैसे- सड़क निर्माण तालाब, खुदाई, नहर निर्माण, जलसंरक्षण, वनीकरण, चेकडैम, खेत, कुंआ निर्माण आदि। ये कार्य गाँव की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए। इससे खेती को सिंचाई के साधन मिले, जल संरक्षण बढ़ा और ग्रामीण जीवन स्तर ऊंचा हुआ।

सामाजिक न्याय और समानता :

नरेगा(NREGA) ने जाति, वर्ग और लिंग की परवाह किए बिना सब को काम का अवसर दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाएं बड़ी संख्या मे इसमें सम्मिलित हुए। यह योजना आर्थिक ही नही वरन सामाजिक दृष्टि से भी क्रान्तिकारी रही। इसने सामाजिक न्याय को मूर्त रूप दिया और लोकतंत्र की जड़ो को गाँव तक मजबूत किया।

कोविड - 19 और नरेगा :

कोविड-19 महाभारी के समय जब शहरो से करोड़ो मजदूर गाँवो की ओर लोट रहे थे तो नरेगा ने उन्हें राहत दी और जीवन-यापन के साधन दिये। उस कठिन समय मे इस योजना के बजट में वृद्धि की गयी। कोविड-19 के दौरान जब विश्व मे त्राहि-त्राहि मची हुई थी तब गांवो ने लाखो मजदूरो और किसानों को आसरा दिया तथा नरेगा (NREGA)ने पेट भरने के लिये रोटी दी। इससे स्पष्ट होता है कि नरेगा भारत के ग्रामीण समाज के लिये जीवन रेखा (Lifeline) है।

सतत विकास में नरेगा की भूमिका :

नरेगा केवल रोजगार योजना नही है, यह सतत विकास लक्ष्यो (SDGs) को हासिल करने का भी माध्यम है। जल संरक्षण हरित विकास, सामाजिक समानता, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य नरेगा के माध्यम से पूरे किए जा सकते है।

नरेगा (NREGA) की उपलब्धिया :

पिछले डेढ़ दशक में नरेगा ने करोड़ो परिवारो को रोजगार दिया। लाखो कुएँ, तालाब, सड़के, सिंचाई नहरे और अन्य परिसंपत्तियाँ बनी। गाँवो मे मजदूरी दर बढ़ी, परिवारो की आय स्थिर हुई जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो को सहारा मिला। महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक होना इसकी सबसे बड़ी सफलता है।

नरेगा (NREGA) की चुनौतियाँ :

नरेगा की अनेक उपलब्धियाँ होने के बावजूद इस योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

1. ग्रामीणों को कई जगह काम मं।गने के बावजूद समय पर रोजगार उपलब्ध नही होता है।स्

2.मजदूरो को समय पर मजदूरी का भुगतान नही होता है।

3.अनेक राज्यो मे भष्ट्राचार और फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले सामने आये है।

4. इस योजना के अर्न्तगत काम की गुणवत्ता और काम के स्थायित्व पर अनेक सवाल उठाये जाते है।

5.इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर मे प्राप्त होने वाली मजदूरी कई बार जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त नही होती है

समाधान की दिशा :

इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिये पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिये तकनीकी साधनो जैसे डिजिटल पेमेंट, आधार आधारित उपस्थिति, जी आई एस मैपिंग आदि के प्रयोग मे वृद्धि की जानी चाहिए। मजदूरी की दर कर को महंगाई सूचकाक से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही इस योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी होनी चाहिए। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, (NREGA), काम पाने के अधिकार को वैधानिक बनाने की प्रक्रिया मे एक ठोस कदम है, जो हमे सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है। इस योजना ने ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना ग्रामीण विकास की आधारशिला है यदि पारदर्शिता, वित्तीय मजबूती और कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएं तो नरेगा आगे आने वाले वर्षो में भारत के ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ सूची :

1.भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय;
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (नरेगा) वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
2. Times of India (lucknow Edition) "Women participation in MGNREGA"touches all time high of 45%. in U.P.

3. NCBI Research Paper " Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: An Assesment" 4.Budget 2019-20, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण रोजगार गारण्टी आबंटन (Economic Times). 5. Times of India (Allahabad Edition (2020) Al to help ensure transparency in MNREGA scheme Implementation.
6. wikipedia Contributors - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 en.wikipedia. org
7. World Bank (2017)
Do Rural Public Works
Programs Work? Impact of NREGA in Karnataka. 8. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (2015) MNREGIA and Poverty Reduction in India.Ophi.org.uk

* डा॰ जयश्री भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा ।
* डा॰ शरद चन्द्र, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा ।